एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 05, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2025)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

ग्रामीण महिला कृषि-उद्यमियों को सशक्त बनाने में माइक्रो क्रेडिट ऋण संस्थानों की भूमिका

*डॉ. पूनम चक्रवर्ती[1] एवं डॉ. अनिल नागवंशी[2]
[1]कृषि विस्तार अधिकारी, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश
[2]अनुसंधानकर्ता, भारतीय मृदा विज्ञानं संस्थान, भोपाल
*संवादी लेखक का ईमेल पता: poonamchakrawarty@gmail.com

ग्रामीण महिला कृषि-उद्यमियों को सशक्त बनाने में माइक्रो क्रेडिट ऋण संस्थानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये संस्थान आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ प्रशिक्षण, बाज़ार तक पहुँच और नया सामाजिक आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आमूलचूल बदलाव संभव हो पाया है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में। हालांकि, परंपरागत रूप से उन्हें वित्तीय संसाधनों, तकनीकी सहायता और निर्णय लेने की शक्ति से वंचित रखा गया है। इस स्थिति में माइक्रो क्रेडिट लेंडिंग संस्थाएं (सूक्ष्म ऋण देने वाली संस्थाएं) एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रही हैं। ये संस्थाएं ग्रामीण महिलाओं को छोटे स्तर पर पूंजी उपलब्ध करवा कर उन्हें कृषि-उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित कर रही हैं।

माइक्रो क्रेडिट क्या है?

माइक्रो क्रेडिट का अर्थ है — बहुत छोटे ऋण, जो विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के लोगों को व्यवसाय प्रारंभ करने या मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। ये ऋण अक्सर बिना किसी जमानत के दिए जाते हैं और विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs), NGOs, और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (MFIs) के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।

ग्रामीण महिला कृषि-उद्यमिता में योगदान

1. **आर्थिक आत्मनिर्भरता:** माइक्रो क्रेडिट संस्थाएं महिलाओं को बीज, खाद, उपकरण, सिंचाई संसाधन, पशुपालन आदि के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध करवा रही हैं। इससे महिलाएं खुद का कृषि व्यवसाय शुरू कर पा रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही हैं।
2. **स्वरोज़गार के अवसर:** इन ऋणों के माध्यम से महिलाएं छोटे स्तर पर कृषि आधारित उद्योग जैसे जैविक खेती, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, फूलों की खेती आदि में जुड़ रही हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हो रहा है।
3. **निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि:** जब महिलाएं खुद कमाई करने लगती हैं, तो उन्हें घरेलू और सामाजिक निर्णयों में अधिक महत्व मिलने लगता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने परिवार तथा समुदाय में सम्मान प्राप्त करती हैं।

4. प्रशिक्षण और नेटवर्किंग के अवसर: कई माइक्रो क्रेडिट संस्थाएं केवल पूंजी नहीं देतीं, बल्कि महिलाओं को कृषि तकनीक, विपणन, वित्तीय प्रबंधन आदि के प्रशिक्षण भी देती हैं। इसके साथ ही, वे SHG या महिला उद्यमी समूह बनाकर उन्हें आपस में जोड़ती हैं, जिससे अनुभव और जानकारी का आदान-प्रदान होता ह

चुनौतियाँ और सुधार की ज़रूरतें

- **ब्याज दरें:** कई माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दर पर ऋण देती हैं, जो दीर्घकाल में महिलाओं के लिए बोझ बन सकता है।
- **साक्षरता और जागरूकता की कमी:** कई बार महिलाएं ऋण की शर्तों को ठीक से नहीं समझ पातीं और गलत निर्णय ले लेती हैं।
- **मार्केट एक्सेस की कमी:** उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में अब भी कई बाधाएं हैं, जैसे परिवहन, बिचौलियों की भूमिका, उचित मूल्य न मिलना आदि।

निष्कर्ष

माइक्रो क्रेडिट लेंडिंग संस्थाएं ग्रामीण महिला कृषि-उद्यमियों के लिए एक उम्मीद की किरण हैं। ये संस्थाएं न केवल आर्थिक सहायता देती हैं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाती हैं। सरकार, समाज और वित्तीय संस्थाओं को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सेवाएं पारदर्शी, सुलभ और टिकाऊ हों, ताकि ग्रामीण भारत की महिलाएं देश के विकास में बराबरी की भागीदार बन सकें।

सुझाव

- सरकारी योजनाओं को माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के साथ जोड़ना
- डिजिटल लोन सुविधा और प्रशिक्षण की शुरुआत
- स्थानीय मंडियों और ई-कॉमर्स तक सीधी पहुँच दिलाना